भारत में चुनाव फेसबुक की परीक्षा

बिंदु गोयल
शीरा फ्रेंकेल

© The New York Times 2019

वर्ष 2015 में फेसबुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशासन के कामकाज में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में बताया था। पर उसके बाद से चुनावों में फेक न्यूज और भ्रमित करने वाली सूचनाओं के प्रसार के कारण फेसबुक की छवि खराब हो गई है।

जब भारत दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के लिए तैयार है, तब वहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर और दूसरी सूचनाओं के साथ फेक न्यूज की भी बाढ़ आई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में और पांच साल मांग रहे हैं, और आगामी 11 अप्रैल से अगले पांच सप्ताह तक होने वाले चुनाव में अनुमानित 90 करोड़ मतदाता मतदान करने वाले हैं। जैसे-जैसे चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर घृणा पैदा करते भाषण और गलत-भ्रामक सूचनाओं की बढ़ोतरी होती जा रही है। विगत सोमवार को फेसबुक ने कहा कि उसने भाजपा और उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के सैकड़ों भ्रमित करने वाले पेज और अकाउंट हटा दिए हैं। फेसबुक ने पाक सेना द्वारा नियंत्रित 100 फेक पेज और अकाउंट भी हटा दिए।

भारत में फेसबुक एक अलग तरह की ही चुनौती का सामना कर रहा है, जहां उसके 34 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया के और किसी भी देश की तुलना में अधिक है। रोज दर्जन भर से भी अधिक भाषाओं के पोस्ट और वीडियो फेसबुक के ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर और उसके मॉडरेटरों को भ्रमित कर देते हैं, जिनकी गति ज्यादातर अंग्रेजी में ही है। समस्या पैदा करते कुछ पोस्ट सीधे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, राजनीतिक पार्टियों और मीडिया की तरफ से आते हैं। और व्हाट्सएप पर शेयर की जाने वाली ज्यादातर चीजों पर कंपनी नजर ही नहीं रख पाती।

दुनिया भर में होने वाले चुनावों की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख केटी हरबाथ कहती हैं, 'भारत में होने वाले चुनाव दूसरी जगहों से अलग हैं, क्योंकि एक तो वहां कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसके अलावा वहां चुनाव कई चरणों में लंबे समय तक चलते हैं।' वह कहती हैं कि भारत के लोकसभा चुनाव को देखते हुए फेसबुक ने एक साल पहले से ही तैयारी की थी। गूगल और यू-ट्यूब जैसे दूसरे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी फेक न्यूज और हेट स्पीच से जूझ रहे हैं। पहली बार भारत के चुनाव आयुक्त ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के चुनाव से संबंधित कंटेंट की जांच करने के लिए कहा है।

लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, जाहिर है, फेसबुक के लिए है, जो 2016 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही निशाने पर है, जब उसने गलत सूचनाएं जाने दी थीं और जिनका रूसी एजेंटों द्वारा दुरुपयोग करने का आरोप है। हालांकि अमेरिका में 2018 में हुए मध्यावधि चुनाव के दौरान फेसबुक पर कोई नया आरोप नहीं लगा था, लेकिन अब भी चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फेसबुक पर विदेशी असर वाले नेटवर्कों की सक्रियता पाई गई है। पिछले साल मैक्सिको और ब्राजील में हुए चुनावों के दौरान भी गलत सूचनाओं के कारण फेसबुक की सेवाओं में परेशानी आई थी।

इस साल भारत में हो रहा लोकसभा चुनाव फेसबुक की सबसे बड़ी परीक्षा है। भारत में फेसबुक का प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वह प्रोपेगेंडा, झूठी खबर और विदेशी असर वाले नेटवर्कों के चंगुल से बचकर निष्पक्षता का परिचय दे पाएगा या नहीं। अटलांटिक काउंसिल स्थित डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च लैब के निदेशक ग्राहम ब्रुकी कहते हैं, 'भारत में हो रहे 2019 के चुनाव फेसबुक के लिए टेस्ट केस हैं कि वह 2020 में कैसे खुद को सही करेगा, और कैसे दुनिया भर में होने वाले चुनावों में निष्पक्षता का परिचय देगा।'

भारत के चुनाव फेसबुक के लिए प्रयोगशाला तो खैर 2014 से ही है। उस चुनाव में फेसबुक ने विज्ञापन हासिल करने और प्रशंसकों को एकजुट करने के लिए नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान के साथ मिलकर काम किया था। तब फेसबुक के सहयोग से ही मोदी सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले राजनेताओं में तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर थे। मोदी की जीत के बाद फेसबुक ने उन्हें सलाह दी थी कि वह प्रशासनिक कामकाज में इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ष 2015 में फेसबुक के मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग ने सिलिकन वैली स्थित कंपनी के मुख्यालय में मोदी की मेजबानी की थी। तब फेसबुक ने कहा था कि सरकारी कामकाज में इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल का भारत एक बेहतर उदाहरण हो सकता है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर भ्रामक सूचनाओं के व्यापक प्रसार को देखते हुए फेसबुक ने बाद में नरेंद्र मोदी समेत दूसरे राजनेताओं से दूरी बना ली। फॉक्स के पूर्व कार्यकारी और विगत जनवरी में फेसबुक के पहले भारतीय प्रमुख बने अजित मोहन कहते हैं, 'हमारा अब भारत समेत दुनिया की किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है।' भारत में कंटेट पर नजर रखने के लिए फेसबुक ने पिछले साल दो संस्थाओं की मदद ली। इनमें से एक तो स्थानीय समूह बूम है, जबकि दूसरी चर्चित न्यूज एजेंसी एएफपी है। विगत फरवरी में फेसबुक ने पांच और संस्थाओं की मदद लेनी शुरू की-अब वह सात भारतीय भाषाओं के कंटेट जांचने में सक्षम है।

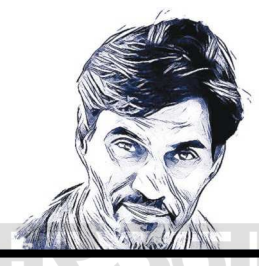

नमस्कार

यशवंत व्यास

शंख और डमरू

कुछ दिनों से यह स्तंभकार छुट्टी पर दिखता रहा। छुट्टी पर 'होना' और 'दिखना' में तकनीकी अंतर है। स्तंभकार चूंकि जनता के बीच से आता है, इसलिए तकनीकी अंतर से तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक कि नैतिक अंतर ही न पड़ जाए। मगर इस हफ्ते आये थोकबंद संदेशों और ज्ञानवाणियों से पता चला कि नैतिकता की भी तकनीक होती है।

तकनीक की छाती पर मूंग दरते हुए, नैतिकता की खिचड़ी तैयार की जा सकती है और नैतिकता की लकड़ी डालकर चिता की जानलेवा तकनीक का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इस बार कवि उसी मार्ग पर मिला। वह नैतिकता का डमरू लेकर जेल की तरफ जा रहा था। मैंने पूछा, यह क्या है? कवि ने कहा, तकनीकी तौर पर यह डमरू होगा, लेकिन नैतिक तौर पर यह शंख है।

'मगर डमरू और शंख की कार्यप्रणाली में खासा फर्क है। एक में सांस भरना पड़ती है, दूसरे में डुगडुगी का इंतजाम है। यह अकेला, दोनों कैसे हो सकता है?'

कवि कोई मामूली न था, सहज रहा। वह अंतर्विरोधों में आनंद को बहुलता की खोज तक निरंतर रख सकता था। बोला, तुम जानते हो - 'बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन' नामक पंक्ति एक इंकलाबी फारसी शायर ने बर्तानवी हुकूमत से क्रांतिकारी सवाल करते हुए लिखी थी।'

डमरू बजाता कवि वाया कलकत्ता, अहमदाबाद, इटावा आया था, दिल्ली घूमता पाटलिपुत्र को निकल गया है। जेल में बंद किसी क्रांतिकारी से जातिविहीन समाज की धर्मनिरपेक्ष संकल्पना पर राय हो जाए तो वह अपने नैतिक मोक्ष को प्राप्त हो।

मैंने कहा, लेकिन वो तो पंतजी जैसे प्रकृतिवादी के कोमल उद्गार माने जाते हैं। कवि ने कहा, तुम्हारी यही समस्या है। तुम अतीत में रुक गए हो। वक्त को देखो, कैसी भयंकर कालिमा दिख रही है। हम एक निर्मम समय में जी रहे हैं। नैतिक यह है कि वह हर पंक्ति जो इस समय को प्रत्युत्तर दे, वह उसी की है, जो क्रांति को प्रस्तुत है, तकनीकी तौर पर चाहे वह किसी की हो।

कवि ने फिर डमरू बजाया और पूछा, शंख ध्वनि आई? मैंने कहा, डम-डम तो मदारी वाली थी।

'अभी तुम्हारा वर्ग चरित्र नहीं बदला। तुम्हें एक और प्रयोग से सिखाने की कोशिश करता हूं। वह देखो, वह क्या है ?'

'विराट फार्म हाउस है। करोड़ों का है, लाखों कमाकर देता होगा।'

'वह मुझे किसी त्यागी राजकुमार की पुश्तैनी जमीन का छोटा-सा टुकड़ा दिख रहा है, जिस पर गरीब बच्चे सपनों में खोये सो रहे हैं। एक दैत्य उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है।'

'मुझे क्यों नहीं दिखाई देता?'

'क्योंकि तुम तकनीकी तौर पर देख रहे हो, मैं नैतिक तौर पर देख रहा हूँ।... और वह देखो, वह क्या है?'

'वह एक विराट मानव समूह है।'

'नहीं, दो समूह हैं।'

'चलो, दो समूह हैं।'

'नहीं, पहले में पांच उप-समूह हैं।'

'चलो, पांच माने। दूसरे होंगे। सबमें होंगे।'

' नहीं, दूसरा अकेला है, पांच में से तीन उसमें मिल गए हैं।'

'आप घपला कर रहे हैं। इसको तोड़कर उसमें मिला रहे हैं। गिनती उलट रही है, दूसरा तीसरा हो गया है।'

'ओह, तुम फिर अटके। क्रांति में तकनीकी तौर पर नैतिक होना अनिवार्य शर्त है।'

कवि ने डमरू को फिर तीन बार फटकार कर बजाया,'अब तो शंख सुनाई दिया?' मुझे तब भी डुग-डुगी ही लगी। उसने जूते उतारे और कहा, 'अहा, ये अद्भुत मंत्रोच्चार सुनाई दिया?' मैंने कहा, कुछ अजीब-सा सुना, शायद-लुच्चा! कवि ने चिढ़ कर कहा, वह सामने देखो क्या बह रहा है? मैंने कहा, गटर! वह बोला, तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया। वह गंगा है।

डमरू बजाता कवि वाया कलकत्ता, अहमदाबाद, इटावा आया था, दिल्ली घूमता पाटलिपुत्र को निकल गया है। जेल में बंद किसी क्रांतिकारी से जातिविहीन समाज की धर्मनिरपेक्ष संकल्पना पर राय हो जाए तो वह अपने नैतिक मोक्ष को प्राप्त हो।

दुष्यंत ने जो शेर कहा था, उसके बारे में कवि कहता है कि वह बच्चन की *मधुशाला* का नैतिक अनुवाद था जो तकनीकी तौर पर तत्कालीन सत्ता की प्रशस्ति में लिखा गया था।

लालू, चौटाला से लेकर रेड्डी, मुकुल और मिशेल तक-सब शंख बजा रहे हैं।

कमाल है, आपको अब भी डमरू सुनाई दे रहा है ?

रॉलेट सत्याग्रह के सौ साल

अभी चुनाव अभियान में जुटे राजनेता छह अप्रैल, 1919 को विरोध को दबाने के लिए लाए गए रॉलेट अधिनियम के विरोध में शुरू किए गए गांधी के सत्याग्रह के संकल्प की भावना से बंध जाएं, तो भारत पहले से अधिक सुरक्षित और खुशनुमा जगह बन जाएगा।

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

तमाम राजनीतिक दलों के नेता इन दिनों वोट जुटाने के लिए देश भर में घूम रहे हैं। आज से ठीक सौ साल पहले 1919 के वसंत में एक नेता देश के विभिन्न हिस्सों में घूम रहा था। तब तक मोहनदास करमचंद गांधी को अपनी मातृभूमि लौटे चार वर्ष हो चुके थे। उन्होंने 1917 में चंपारण में और 1918 में खेड़ा में किसान आंदोलन को चलाया था और अहमदाबाद में मिल के कामगारों के एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब वह अपने पहले अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे थे, जिसका मकसद था उत्पीड़न करने वाले रॉलेट अधिनियम का विरोध। इस कानून के तहत विरोध को अपराध माना जाता था और कथित विरोधियों के खिलाफ बिना जजों के बंद कमरे में प्रेस और आम लोगों की गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकता था।

गांधी ने आठ फरवरी, 1919 को अपने एक भारतीय सहयोगी को लिखा कि रॉलेट बिल सच्चाई से दूर रहने का कोई अकेला उदाहरण नहीं हैं, बल्कि यह उत्पीड़न की कठोर नीति का भी प्रमाण हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वतंत्रता से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह नागरिक अवज्ञा के लिए आगे आए। ठीक उसी दिन उन्होंने अपने एक दक्षिण अफ्रीकी दोस्त को लिखा : रॉलेट बिलों ने मुझे बेहद क्षुब्ध कर दिया है। ऐसा लगता है कि मुझे मेरे जीवन की महान लड़ाई लड़नी ही होगी। फरवरी, 1919 के आखिरी हफ्ते में गांधी ने अहमदाबाद में अपने आश्रम में देशभक्तों की एक बैठक बुलाई। इसमें 'सत्याग्रह संकल्प' का एक मसौदा तैयार किया गया। इसमें दस्तख्त करने वालों ने संकल्प लिया कि यदि दोनों रॉलेट बिल वापस नहीं लिए गए, तो वे गिरफ्तारी देंगे। इस बीच, गांधी ने वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा और उनसे बिलों को वापस लेने के लिए कहा, क्योंकि सबसे निरंकुश (सरकार) को भी आखिरकार ताकत तो शासित लोगों की इच्छा से ही मिलती है।

वाइसराय ने बिलों को वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांधी ने अपने सत्याग्रह संकल्प पर लोगों का समर्थन और उनके हस्ताक्षर हासिल करने के लिए देश भर का भ्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने लखनऊ, इलाहाबाद, बॉम्बे और मद्रास के साथ ही कई छोटे शहरों की भी यात्रा की। वह रविवार छह अप्रैल, 1919 को प्रस्तावित देशव्यापी अवज्ञा के लिए अपने बढ़ते समर्थकों को तैयार कर रहे थे।

उस वक्त बॉम्बे भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था। सो, गांधी ने इस शहर में प्रदर्शन का नेतृत्व अपने हाथ में रखने का फैसला किया। वह सुबह 6.30 बजे चौपाटी तट पर पहुंचे। उनके समर्थकों ने समुद्र में स्नान किया और उनके आसपास बैठ गए। सुबह आठ बजे तक वहां लोगों का हुजूम लग गया और वे सब समुद्र की ओर मुंह करके बैठ गए। एक रिपोर्टर ने अनुमान लगाया कि '1,50,000 लोग मौजूद थे, जिनमें मुसलमान, हिंदू, पारसी आदि और एक अंग्रेज शामिल था।'अपने भाषण में गांधी ने हाल ही में दिल्ली में सत्याग्रहियों पर हुई पुलिस गोलीबारी की निंदा की और फिर भीड़ से बोले कि वह वाइसराय को भेजे जा रहे रॉलेट ऐक्ट वापस लेने से संबंधित संकल्पों का समर्थन करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेगुनाहों के खून से इसका महत्व बढ़ गया, हम वादा करते हैं कि हम तब तक नागरिक अवज्ञा करते रहेंगे, जब तक कि शासकों का दिल नहीं पसीज जाता।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह वास्तव में पहला अखिल भारतीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति में देश का बड़ा हिस्सा अछूता रहा था। यह उल्लेखनीय है कि जहां पैमाने, तीव्रता और चरित्र के मामले में प्रदर्शनों में भारी भिन्नता थी, लेकिन इन सबमें एक चीज समान थी और वह थी, हिंदू-मुसलिम सद्भाव का प्रदर्शन। इसीलिए सत्याग्रह को भारी कामयाब बताते हुए, बॉम्बे से छपने वाले एक उर्दू साप्ताहिक ने दर्ज किया कि सरकार द्वारा पारित विधेयकों ने हिंदुओं और मुसलमानों को चीनी और पानी की तरह आपस में मिला दिया, जबकि एक बार ये दोनों समुदाय एक दूसरे से अलग हो गए थे और उनमें लंबे समय तक मतभेद कायम रहे।

इस बीच, कराची के एक अखबार ने पाया कि 'तटीय शहर की दुकानें और व्यावसायिक केंद्र बंद थे : आखिर इस शहर के इतिहास में ऐसी विलक्षण घटना पहले कब हुई? अखबार ने आगे लिखा : 'कल के कार्यक्रम से कोई भी इस बात को लेकर प्रभावित हो सकता है कि वहां सांप्रदायिक, संकीर्ण और विभाजनकारी भावनाएं नदारद थीं। वे कल हिंदू, मुसलमान, पारसी, खोजा, जैन रहे होंगे, पर उन सबने महसूस किया कि वे एक समुदाय से संबंध रखते हैं- भारतीय; उन सबने महसूस किया कि विभिन्न धर्मों में एक धर्म है और वह है आत्म सम्मान का धर्म, मानवता की सेवा करने से संबंधित भारत के अधिकार की रक्षा करने का धर्म।'

रॉलेट सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रवाद और महात्मा गांधी के जीवनी लेखकों के लिए विशेष रुचि का विषय है। (इच्छुक पाठक रविंद्र कुमार द्वारा संपादित किताब, *ऐसेस इन गांधियन पॉलिटिक्स* देख सकते हैं, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों के शोधपरक आलेख शामिल किए गए हैं।) हालांकि हमारे इस विभाजित समय में रॉलेट सत्याग्रह इस बिरादरी के लिए प्रासंगिक है।

मैंने अखबारों में छपी रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, जो इस बात का प्रमाण हैं कि रॉलेट सत्याग्रह के समय भारतीयों ने किस तरह से अपने धार्मिक मत और समुदाय के मतभेदों को परे कर दिया था। अब मैं इस आंदोलन के नेता के हवाले से ही बात रखना चाहता हूं। आंदोलन के दौरान गांधी ने भारतीय राष्ट्रवादियों से कहा कि वह ये संकल्प लें :

'ईश्वर को साक्षी मानकर हम हिंदू और मुसलमान यह घोषणा करते हैं कि हम एक दूसरे प्रति ऐसा भाव रखेंगे जैसे हम एक ही अभिभावक की संतानें हैं, हमारे बीच कोई भेद नहीं होगा, एक का दुख दूसरे का दुख होगा और हर कोई दूसरे का दुख दूर करने में मदद करेगा। हम एक दूसरे के धर्म और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे की धार्मिक आस्था की राह में आड़े नहीं आएंगे। हम धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हिंसा से हमेशा बचेंगे।'

रॉलेट सत्याग्रह के दौरान अंतर सामुदायिक एकजुटता की भावना जिस तरह से मजबूती से नजर आई थी, वैसा गांधी के नेतृत्व में हुए बाद के आंदोलनों में नजर नहीं आई। खुद उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया और इस पर दुख जताया और अपने अंतिम वर्षों को इसी भावना को दोबारा प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह के एक सौ वर्ष बाद हमें नेताओं पर ऐसा ही आचरण करने का दबाव बनाना चाहिए। यदि अभी चुनाव अभियान में जुटे राजनेता गांधी के अप्रैल, 1919 के पवित्र संकल्प की भावना से बंध जाएं तो भारत निश्चित रूप से पहले से अधिक सुरक्षित और खुशनुमा जगह बन जाएगा।

मुश्किल वैश्विक चुनौतियों के बीच मोदी

कृषि संबंधी दुश्वारियों और नोटबंदी के बाद पैदा हुई दिक्कतों के बावजूद लोकसभा चुनाव में लगता है कि मतदाता खंडित जनादेश नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ने संक्रमण में भी बेहतर काम किया है।

बिंदू डालमिया

लोकसभा चुनाव में करीब 90 करोड़ मतदाता अब वोट देने के लिए तैयार हैं। चुनावी मौसम मई तक जारी रहेगा। पिछले कुछ दिनों में हवा भाजपा की ओर बहती हुई साफ नजर आई है। बेशक कृषि संबंधी दुश्वारियों और नोटबंदी के बाद पैदा दिक्कतों के बाद भी वोटर मोदी की ओर झुकता लग रहा है। लगने लगा है कि वह खंडित जनादेश नहीं देगा, जिससे राहुल गांधी, ममता बनर्जी या मायावती जैसे नेताओं के लिए राह बन सके, जो केंद्र में सरकार चलाने के लिए अनुभवहीन हैं।

मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का कार्यकाल खत्म होने की ओर है। यह जानना चाहिए कि रोजगार पैदा करने में कमी और किसानों से जुड़ी दिक्कतों के लिए क्या वाकई मोदी सरकार जिम्मेदार है। इन बातों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए।

अब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा पहलू बन गई, जिसने लोगों की भावनाओं को मजबूत और बहुमत वाली सरकार लाने की ओर मोड़ने का संकेत दिया है। राष्ट्रवाद का मुद्दा एनडीए के लिए अनुकूल है, साथ ही, इससे मोदी के पक्ष में हवा का रुख हो गया। पर यह समय ऐसा भी है, जब सत्तारूढ़ पार्टी को असहज सवालों को ठंडे बस्ते में डालने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। नोटबंदी, रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर उसे रक्षात्मक होने के बजाय असलियत बताने की जरूरत है।

मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि उसने सोशल सेक्टर में तगड़ा काम किया है-इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। सौ फीसदी बिजली गांवों तक पहुंची, तो 90 फीसदी इलाके में साफ-सफाई का काम पूरा हो गया। ग्रामीण भारत में 3,12,526 किलोमीटर तक डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाया गया। माना जाने लगा है कि भाजपा 240 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। यानी मोदी को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। हां, जनता से जुड़े मुद्दों पर तेज फोकस और डिलिवरी के लिए दमदार नीति की जरूरत होगी, क्योंकि सभी का ध्यान अबकी बार इसी ओर होगा। ध्यान रखना चाहिए कि अगर वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक न हो, तो कोई भी देश इस बहाव के खिलाफ नहीं चल सकता। इस समय भी आर्थिक मंदी सरीखे हालात हैं। हमें पिछले तीन सालों में नोटबंदी के कारण पैदा प्रभावों को देखना चाहिए। हर देश जब भी कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाता है, तो कुछ दर्द से गुजरना ही होता है। हमें समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करना ही होगा। नोटबंदी अकेला सुधार नहीं था। इसमें बेनामी संपत्ति में पारदर्शिता लाने की बात भी थी। बैंकों को भी ज्यादा जवाबदेह बनाने की बात की गई, ताकि वह

हर कर्ज को ठोक-बजाकर पास करें। बेशक नोटबंदी को घरेलू सिस्टम में सुधार के लिए उठाया गया था। इससे हमारी जीडीपी में टैक्स आधार का अनुपात 17 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है। टैक्स देने के मामले में असमानता दूर करने की जरूरत है। जब राजस्व बढ़ेगा, तो सामाजिक और भौतिक संरचना बेहतर की जा सकेगी।

वैश्विक हालात भी रोजगार पैदा करने में आड़े आ रहे हैं। वैश्विक मंदी से निर्यात कम हो रहा है। यही नहीं, एक तिहाई नौकरियां अगले तीन साल में ऑटोमेटेड हो जाएंगे। मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि गुड्स सेक्टर के बजाय सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। विश्व बैंक का अध्ययन बताता है कि ऑनलाइन इकोनॉमी 2020 तक बढ़कर 25 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। ऐसे में ऐसी शिक्षा की जरूरत होगी, जो रोजगार बाजार की नई चुनौतियां समझे। मोदी सरकार भी उस ग्लोबल ट्रेंड के खिलाफ नहीं जा सकती, जिसमें रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा।

कृषि पर निर्भरता भी कम करने की जरूरत होगी। अर्थव्यवस्था की तीसरी बड़ी चुनौती कृषि ही है। अब सभी विकासशील देश कृषि पर जीडीपी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होगी, उसके साथ जीडीपी पर कृषि का असर भी कम होना चाहिए। दक्षिण कोरिया में यह दो फीसदी, ताइवान में 1.6 फीसदी, जापान और अमेरिका में एक-एक फीसदी और ब्रिटेन में आधा फीसदी है। जबकि हमारे देश में आधी आबादी अब भी कृषि आय पर निर्भर करती है। इसके जरिये 9-10 फीसदी जीडीपी की विकास दर हासिल होती है। हालांकि कृषि के नए तौर-तरीकों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। नई तकनीक से लेकर बेहतर मार्केटिंग, सही मूल्य और ऋण सिस्टम की जरूरत है। ध्यान रखना चाहिए कि कृषि को हमने 60 साल से लगभग उपेक्षित ही कर रखा है। लेकिन इसका असर 2019 में ज्यादा महसूस किया गया। नाबार्ड के एक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रति हेक्टेयर जोत आमदनी प्रति माह केवल 1,300 रुपये से 3,000 रुपये रही। आजादी के बाद हमारी नीतियां ऐसी रहीं कि कृषि मजदूर शहर की ओर पलायन करते रहे। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित रोजगार सृजन की जरूरत है।

नरेंद्र मोदी का पांच साल का कार्यकाल 73 साल पुराने इस देश में बहुत छोटा कहा जाएगा। हालांकि इस दौर में उन्होंने आर्थिक सुधार के संकेत दिखा दिए हैं। इसी दौरान आयुष्मान भारत और सोशल सेक्टर इनवेस्टमेंट्स जैसी योजनाएं लाई गई हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपाय किए जा सकें, रोजगार पैदा हो सके और कृषि आधारित आय पर आवश्यकताएं कम हों। ऐसे में कहना चाहिए कि मोदी सरकार ने संक्रमण में भी बेहतर काम किया है।